Persons apprehended in Purulia incident

227. SHRIMATI MALTI SHARMA:
SHRI RAJ NATH SINGH:
SHRI V. NARAYANASAMY:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of persons who had been arrested in the Purulia district of West Bengal while they were dropping ammunition and foreign made gun and other arms; and

(b) the action being taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SYED SIBTEY RAZI): (a) 25 persons, allegedly involved in the dropping of arms and ammunition in Purulia District of West Bengal, have been arrested so far.

(b) Investigation is being conducted by the CBI to collect evidence about the role of the arrested persons and others in the case. For the apprehension of other suspects, INTERPOL references have been made, look out notices have been issued, exit points in India have been alerted, intelligence has been geared up and field investigation is being conducted in various parts of the country. Non-bailable warrants of arrest have been issued by the Court of Law against three others allegedly involved in the incident.

तेल क्षेत्र में संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

228. **श्री अजीत जोगी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के तेल क्षेत्रों के कुछ ब्लाकों को संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को सौंपने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ विदेशी पूंजी निवेश आमंत्रित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन विदेशी एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है जिनसे पूंजी निवेश आमंत्रित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) से (ङ) अगस्त, 1992 में खोजे गए क्षेत्रों के पहले प्रस्ताव में सरकार ने संयुक्त उद्यम व्यवस्थाओं के अंतर्गत 5 मध्यम आकार के क्षेत्रों के लिए निम्नानुसार ठेके देने का अनुमोदन किया:

कंपनी/परिसंघ का नाम	राज्य	मध्यम आकार के क्षेत्र
1. एनरान-यू०एस०ए०, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत	बम्बई अपतट	मध्य और दक्षिण ताप्ती, मुक्ता और पन्ना।
2. कमांड पेट्रोलियम-आस्ट्रेलिया, वीडियोकान-भारत, मारूबेनी-जापान	कृष्णा गोदावरी अपतट	राव्वा
3. कंपनी जियोपाइनेन्सियर-फ्रांस, एनप्रो सर्विसेज-भारत	अरुणाचल प्रदेश	खरसांग

उपर्युक्त सभी संविदाओं पर हस्ताक्षण कर लिए गए हैं। विदेशी कंपनियों द्वारा इन क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 500 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने का अनुमान है।

संयुक्त उद्यम व्यवस्थाओं के अंतर्गत 8 मध्यम आकार के क्षेत्रों का दूसरा प्रस्ताव अक्तूबर, 1993 में किया गया। 7 मध्यम आकार के क्षेत्रों के लिए 34 बोलियां प्राप्त हुईं। यह सरकार के विचाराधीन हैं।

संयुक्त उद्यम अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत 28 अन्वेषण ब्लाकों का एक और प्रस्ताव 1995 में किया गया। 7 ब्लाकों के लिए 22 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह सरकार के विचाराधीन हैं।

Policy for grant of fishing permits

229. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the present policy of Government with regard to grant of fishing permits;

(b) whether Government have cancelled all permits/lease granted to private individuals and also to joint sector on *fishing*;

(c) the financial implication of the present and revised deep sea fishing policy; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) The New Deep Sea Fishing Policy 1991, includes shcemes for Joint Venture, Leasing and Test Fishing for operation of deep sea fishing vessels in the Indian Exclusive Economic Zone. Apart from this, chartering of foreign vessels was allowed under charter policies of 1981 and 1986, which have been phased out and permits are being issued only in respect of the cases where it is legally warranted to grant the same.

(b) No, Sir. However, a committee constituted for making recommendations for the review of deep sea fishing policy has submitted its report on 8th February, 1996. Action has been initiated at inter-Ministerial level to examine the recommendations of this Review Committee.

(c) and (d) As the deep sea fishing policy has not been revised, the question of financial implication in case of its revision does not arise at present.

पुलिस के काम-काज के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए विधिक निकाय की स्थापना

230. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुलिस के काम-काज के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए एक विधिक निकाय की स्थापना करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० कामसन): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) भाग को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Collaboration with American companies in food processing industries

231. SHRI RAM NATH KOVIND: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian and American companies have decided to develop greater collaboration in the food processing industry;

(b) whether Government have granted permission for the collaboration of the Indian companies with the American companies; and